जलवायु प्रक्रियाओं में राष्ट्रवादी बाधा

लेखक - नवरोज के. दुबाश (प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

23 सितम्बर, 2019

"ऐसी संभावना है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन राष्ट्रवाद के युग में जलवायु राजनीति के बारे में कठिन सबक प्रदान करेगी।"

क्या वैश्विक कूटनीतिक लोकप्रिय युवाओं के उत्थान के समर्थन में राष्ट्रों के कठिन आर्थिक और राजनीतिक गणना को स्थानांतरित कर सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई गई और ऊर्जावान रूप से समर्थित आज की ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट में सिर्फ इसी मुद्दे को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। यह विभिन्न देशों की प्रतिज्ञाओं को बढ़ावा देना चाहता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रों द्वारा की जा रही लापरवाही को संबोधित करता है। इस आलेख में हम इस प्रयास के सफल होने की संभावना कितनी है और इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष क्या हैं उसके बारे में जानेंगे।

दर्शनीय संकेत और विज्ञान

यह शिखर सम्मेलन वैज्ञानिकों द्वारा दी गयी चेतावनी के बाद सामने आयी है। शिखर सम्मेलन के वैज्ञानिक सलाहकार समूह (जिनमें से मैं भी एक सदस्य हूं) की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 के बाद से पांच साल किसी भी दर्ज की गई अवधि की तुलना में सबसे गर्म रहा है, समुद्र के स्तर में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है और महासागर औद्योगिक युग के उदय के कारण 26% अधिक अम्लीय हो गए हैं। हाल की मौसम की घटनाओं से हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देख सकते है। इस गर्मी में दक्षिणी यूरोप में दिल्ली जैसा तापमान देखा गया; तूफान 'डोरियन' ने बहामास के बड़े हिस्सों को अप्राप्य बना दिया; और अमेजॅन, मध्य अफ्रीका और यहां तक कि साइबेरिया में भी एक साथ भयंकर आग की घटना देखी गई।

वैज्ञानिक इन घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ने में सक्षम हैं - फ्रांस और जर्मनी में गर्मी की लहर जलवायु परिवर्तन के कारण आठ से 10 गुना अधिक थी। फिर भी, विश्व भर में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि जारी है और वर्तमान में सभी देशों के लक्ष्य के बावजूद 2030 तक इसकी वृद्धि नहीं रुकेगी।

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रमाण ने युवाओं में विशेष रूप से सामाजिक कार्रवाई को बढ़ावा दिया है। वैश्विक उत्तर के साथ-साथ युवा लोग भारत और अन्य देशों में वैश्विक दक्षिण में भी जुट रहे हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि आयोजकों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता के खिलाफ (शुक्रवार को) विश्व भर में चार मिलियन युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

राजनीतिक अलगाव

वर्तमान में विज्ञान, अनुभव और सार्वजनिक अलार्म कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि राष्ट्रों द्वारा इस संदर्भ में कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। कई देशों में राष्ट्रवाद की ओर झुकाव ने जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए आवश्यक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के लिए एक ऐसी अल्पकालिक और खुद का भला सोचने वाली मानसिकता को जन्म दिया है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए आवश्यक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के लिए हानिकारक है।

इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न केवल कार्रवाइयों को बढ़ाने से इंकार कर दिया, बल्कि उन्होंने बिजली क्षेत्र में सक्रिय रूप से कई कदम वापस लिए हैं और प्रतिस्पर्धा के नाम पर मीथेन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए

कार्रवाई की है। ब्राजील में, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने स्पष्ट किया है कि वे पर्यावरण संरक्षण को ब्राजील के व्यापार को सीमित करने के रूप में देखते हैं। और कुछ देशों में राष्ट्रवाद उन देशों में भी आक्रामक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कठिन बनाता है, जहां राजनीति अधिक अनुकूल है।

अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों और लोगों में बढ़ती जागरूकता के आधार पर, क्या संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन उन्नत कार्रवाई की ओर राष्ट्रों का झुकाव बढ़ा सकता है? इस प्रश्न के संदर्भ में महासचिव दो-ट्रैक दृष्टिकोण के आधार पर आशा जाहिर करते हैं।

सबसे पहला, राजनयिक दबाव के अभ्यास में, देशों से पेरिस समझौते के हिस्से के रूप में किए गए कार्यों के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को बढ़ाने का आग्रह किया गया है, जिससे भविष्य के उत्सर्जन में कमी आए। इसका आशय यह है कि क्लाइमेट चौम्पियन को एक महत्वपूर्ण वैश्विक एजेंडा का नेतृत्व करने और दावा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

हालांकि, अब तक प्रतिक्रिया सकारात्मक प्रभाव डालने में नाकाम रही है। यूनाइटेड किंगडम सहित कई छोटे और मध्यम आकार के देशों ने पहले ही 2050 तक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को शुद्ध कार्बन तटस्थ बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। इसके विपरीत, कई बड़े देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और मैक्सिको ने कथित रूप से इस कार्यक्रम में उच्च स्तर पर भाग लेने से मना कर दिया हैं। चीन और भारत ने यह कहते हुए बयान जारी किए हैं कि वे काफी काम कर रहे हैं और भारत ने यह भी कहा है कि उसे इस संदर्भ में और अधिक कार्य करने के लिए वित्त की आवश्यकता होगी।

दूसरा, कूटनीति के दायरे में कम संचालित होता है और 'एक्शन पोर्टफोलियो' के एक सेट के आसपास वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव के लिए प्रेरित करता है। 'इनमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए कम कार्बन ऊर्जा की ओर एक ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाना और इसे तेज करना, शहरों को अधिक जलवायु अनुकूल बनाना और जलवायु विघटन के लिए अधिक लचीला बनाना, साथ ही इस्पात तथा सीमेंट जैसे अधिक ऊर्जा गहन क्षेत्रों को कार्बन के अनुकूल बनाना। विशेष रूप से, घरेलू उद्देश्य इन लक्ष्यों के लिए अधिक उपयुक्त हैं अर्थात ऊर्जा सुरक्षा कारणों से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना; शहरों को अधिक रहने योग्य बनाना; और उद्योगों को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बनाना। ये पहल व्यापार और शोधकर्ताओं के गठबंधन सहित व्यापक बातचीत के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करती है। यदि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में कोई ठोस कार्रवाई होती है, तो यह सबसे उपयोगी साबित हो सकता है।

भारत के लिए रास्ता

वैश्विक जलवायु राजनीति का यह परिदृश्य भारत के लिए क्या मायने रखता है? पहला, यह है कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्रभावी वैश्विक कार्रवाई की संभावनाएं कमजोर हैं, जो भारत के लिए बेहद बुरी खबर है। हम जलवायु प्रभावों का सामना करने वाले सबसे संवेदनशील देश हैं।

दूसरा, भारत के पास अपने विकास हितों को आगे बढ़ाते हुए भी जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई में तेजी लाने के लिए नए उपाय ढूंढने होंगे। एक उल्लेखनीय उदाहरण इसकी ऊर्जा दक्षता ट्रैक रिकॉर्ड है, जो देश की ऊर्जा की बचत करते हुए भी ग्रीनहाउस गैसों को सीमित करने में मदद करता है। हालांकि, एक क्लाइमेट चौंपियन के रूप में भारत की कहानी में कई विसंगतियां हैं। भारत को अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उचित मान्यता प्राप्त है, फिर भी भविष्य के कोयले के उपयोग पर मिश्रित संकेत भेजकर यह स्थिति को विकट बना देती है।

भारतीय प्रधानमंत्री के हालिया सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन (यू.एस. ऑयल कैपिटल) की पसंद, यह संकेत देती है कि भारत अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता को जीवाश्म ईंधन के उपयोग के साथ जोड़कर देखता है। भारत को ऐसी घरेलू ऊर्जा नीतियों की आवश्यकता है, जो भविष्य में कम कार्बन वाले विश्व में अधिक स्पष्ट और सुसंगत हों।

तीसरा, इस तरह का घरेलू संदेश भारत को एक वैश्विक जलवायु नेता के रूप में खड़ा करेगा, न कि केवल जलवायु पिछड़ों के बीच एक नेता के रूप में। क्या भारत, कम कार्बन वाले भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है, जो विकास को बढ़ावा दे?

उदाहरण के लिए क्या भारत और चीन, जहाँ दोनों अफ्रीकी देशों में अपने प्रभुत्व के लिए जूझ रहे हैं लेकिन दोनों जलवायु प्रभावों से हारे हुए हैं, संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि अफ्रीका का विकास जीवाश्म ईंधन के बजाय अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित हो? इस तरह का एजेंडा आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक लाभ को एक साथ ला सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रवाद के दौर में जलवायु राजनीति के बारे में हमें कठिन सबक मिलने की संभावना है। यह लक्ष्य ऊर्जा और शहरीकरण जैसे तेजी से बदलते क्षेत्रों में प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रीय हित की एक प्रबुद्ध धारणा के साथ त्वरित जलवायु कार्रवाई को एकीकृत करना होना चाहिए। इस तरह का मार्ग भारत के लिए आकर्षक संभावनाओं का निर्माण करता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भारत अपने घरेलू विकास मार्ग पर एक कारक के रूप में गंभीर रूप से जलवायु परिवर्तन वाली एक दृढ़ घरेलू नींव पर एक राजनयिक दृष्टिकोण का निर्माण करे।

GS World टीम...

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly)

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि जब दुनियाभर के नेता संयुक्त राष्ट्र के न्यूयार्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करेंगे तब जलवायु परिवर्तन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, 'हम प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के लिए खतरा बने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विशेष ध्यान देंगे।'
- गुटेरस 23 सितंबर को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जलवायु की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए 2019 क्लाइमेट एक्शन समिट की मेजबानी करेंगे।
- देशों और सरकारों के प्रमुख, सदस्य देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और टीन एज कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौजूदा समय के निर्णायक बताए जा रहे मुद्दे से निपटने के उपायों पर विचार करेंगे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लेंगे।

क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के तहत 1945 में इसकी जनरल असेम्बली यानी महासभा स्थापित की गई।
- यह महासभा संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श और नीति निर्माण जैसे मुद्दों पर प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती है।
- 192 सदस्यों से बनी यह संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने चार्टर के तहत कवर किये गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुआयामी और बहुपक्षीय चर्चा के लिये एक बेहतरीन मंच प्रदान करती है।

अध्यक्ष का चुनाव

- महासभा के प्रत्येक अधिवेशन के तीन महीने पहले सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। वर्ष 2003 तक अध्यक्ष अधिवेशन के पहले सम्मेलन में ही चुन लिया जाता था।
- आरंभिक दो सप्ताहों के लिए, सामान्य विवाद जारी रहते हैं, जिसमें महासचिव और अध्यक्ष के बाद हर प्रतिनिधि को सभा के सामने व्याख्यान देने का अवसर प्रदान किया जाता है।

महासभा के कार्य

- 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार प्रयोग से उत्पन्न राष्ट्रसंघ की अकर्मण्यता के निवारण के लिए महासभा ने 1940 में 'लघुसभा' नामक एक अंतरिम समिति की स्थापना की थी।

- महासभा के सत्रावसान में महासभा का कार्य लघुसभा कर सकती है और महासभा का अधिवेशन बुला सकती है। इसके अनुसार, सुरक्षा परिषद में शांति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर एकसमान मत न होने पर, 24 घंटे की सूचना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जो सामूहिक उपायों का प्रस्ताव और सैनिक कार्यवाही का निर्देश कर सकता है।
- 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' ने पिछले वर्षों में विश्व की विभिन्न जटिल समस्याओं पर विचार किया और कोरिया, ग्रीस, पैलेस्टाइन, स्पेन आदि के प्रश्न पर उचित कार्यवाही की।
- 1959 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल द्वारा स्वेज पर किए गए आक्रमण को रोकने में महासभा सफल हुई।

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर यूएन की इस अहम बैठक में बोलेंगे। इसके अलावा वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे।
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी।
- इस दौरान उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अहम बैठक होने जा रही है।
- संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के दो भाषण होंगे, जिनका पूरी दुनिया को इंतजार है। भारत ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो काम किया है, उसकी पूरी दुनिया में धूम है। BS6 में परिवर्तन करने का हो, वनक्षेत्र बढ़ने का हो।
- पेरिस समझौते के पालन पर आगे बढ़ रहा है। और बहुत सारे नए प्रयोग भी किए हैं। जैसे ई-मोबिलिटी को बढ़ाने पर फोकस किया है। तो ये सारी बातें वहां आएंगी। बाकी और फोरम भी वहां होंगे। उसमें हम भाग लेंगे।
- इस सम्मेलन में देशों की सरकारों, निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी, स्थानीय प्रशासनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और छह क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी समाधान तलाश करने के प्रयास किए जाएंगे:-
- वैश्विक स्तर पर नवीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ना
- टिकाऊ व मजबूत बुनियादी ढाँचे व नगर
- टिकाऊ कृषि
- वनों व समुद्रों का प्रबंधन
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए मजबूती और लचीलापन
- नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के साथ सार्वजनिक और निजी वित्तीय संसाधनों का आवंटन

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **वर्ष 2015 के बाद से पांच साल किसी भी दर्ज की गई अवधि की तुलना में वर्ष 2019 सबसे अधिक गर्म रहा है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों पर विचार कीजिए-**

   1. समुद्र के जल स्तर में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है।
   2. औद्योगिक युग के विकास के कारण महासागर 28% अधिक अम्लीय हो गए हैं।
   3. विश्व भर में मिथेन की सांद्रता में कमी जारी है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन असत्य हैं?

   (a) 1 और 3 (b) 2 और 3
   (c) 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **The year 2019 has been recorded the hottest year compared to any equivalent recorded period since 2015. Consider the reasons responsible for this-**

   1. The sea level is rising rapidly.
   2. Due to the development of the industrial age, the oceans have become 28% more acidic.
   3. Methane concentration has continued to decrease worldwide.

   Which of the above statements are incorrect?

   (a) 1 and 3 (b) 2 and 3
   (c) 1 and 2 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः 'वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सबसे बड़ी बाधा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा स्व-हित में सामूहिक उत्तरदायित्व से पीछे हटना है।' इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

Q. 'The biggest obstacle to fighting climate change at present is the withdrawal of collective responsibility by various nations in self-interest.' Analyze this statement.

(250 Words)

नोट : 21 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।